



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 21 नवम्बर, 2008 / 30 कार्तिक, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

LOCAL AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th November, 2008

No.1-73/70-Fin (LA) Vol-6.— On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion Shri B.R.Vaidya, Deputy Controller to the post of Joint Controller in the pay scale of Rs.10025-15100, with immediate effect.

2. Consequent upon the above promotion, Shri B. R. Vaidya will continue to be posted in the Resident Audit Scheme, H.P. Board of School Education, Dharamshala.

3. The above promotion will, however, be subject to the final out come on the Writ Petition (Civil) No. 61/2002 titled M. Nagaraj & Ors. Versus Union of India & Ors and Writ Petition (Civil) No.295/2002- titled Devi Ram Tanwar & Ors. Versus Union of India & Ors in the Hon'ble Supreme Court of India.

4. Shri B.R. Vaidya will remain on probation for a period of two years. He may exercise option for his fixation of pay in the above post within one month from the date of this notification.

By order
ARVIND MEHTA,
Secretary (Finance).

INDUSTRIES DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-2, the 18th November, 2008*

No. Ind-A(B)2-1/2006-I.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order the retirement of Shri Uma Kant Gupta, Mining Officer from Govt. service on 31-1-2009 (AN) on attaining the age of superannuation.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary.

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला, 6 अक्टूबर, 2008

संख्या: सिंचाई-11-03/2008-शिमला.—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव वासा बगैण, तहसील ठियोग, जिला शिमला में उठाऊ पेयजल योजना बगैण पम्प हाऊस के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित है, या हो सकते हैं, कि जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शिमला, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं० | क्षेत्र हैक्टेयर में |
|-------|-------|-----------|----------|----------------------|
| शिमला | ठियोग | वासा बगैण | 283 | 0-08-30 |
| | | | 284 | 0-04-23 |
| | | | 286 | 0-11-94 |
| | | | किता- 3 | रकबा 0-24-47 है० |

शिमला, 25 अक्टूबर, 2008

संख्या: सिंचाई-11-52/2008-बिलासपुर.—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव रन्डोह, में उठाऊ पेयजल योजना पन्थाला सप्लाई टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

1. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित है, या हो सकते हैं, कि जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

2. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

3. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं० | क्षेत्र हैक्टेयर में |
|----------|----------|--------|--------------|----------------------|
| बिलासपुर | घुमारवीं | रन्डोह | 157 / 73 / 1 | 0-08 |

शिमला, 25 अक्टूबर, 2008

संख्या: सिंचाई-11-54/2008-बिलासपुर.—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव सुन्गल, में पेयजल योजना नया बिलासपुर (शहर) में स्टोरेज टैंक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

1. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित है, या हो सकते हैं, कि जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

4. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

5. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

| जिला | तहसील | गांव | खसरा नं० | क्षेत्र हैक्टेयर में |
|----------|-------|--------|----------|----------------------|
| बिलासपुर | सदर | सुन्गल | 176 | 1-13 |

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव ।

सूचना प्रौद्योगिक विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला 18 नवम्बर, 2008

संख्या आई0टी0.ए(3)—3 / 2004.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद—309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में संयुक्त निदेशक, वर्ग—1 (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न **उपाबन्ध—क** के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग संयुक्त निदेशक, वर्ग—1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 है ।

2. ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
सचिव ।

उपाबन्ध —“क”

हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी, वर्ग—1 (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1. **पद का नाम.**—‘संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी’
2. **पद / (पदों) की संख्या.**—01 (एक)
3. **वर्गीकरण.**—वर्ग—1 (राजपत्रित)
4. **वेतनमान.**—13500—400—15900—450—16800रूपए
5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**— चयन
6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**— 18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगम तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेसन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्पूर्वी ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेसित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं—अनिवार्य अर्हता.—(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग (बी0 टैक0/बी0 ई0/एम0सी0ए0 की व्यावसायिक उपाधि या डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 (डोएक) सोसाइटी से 'बी' स्तर का कोर्स या (एक वर्ष के अतिरिक्त अनुभव के साथ) पी0जी0डी0सी0 ए0 सहित विज्ञान स्नातकोत्तर।

(ii) सरकारी/नियमित/प्राइवेट सेक्टर में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष का अनुभव।

2. वाँछनीय अर्हता(एँ).—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.— आयु.—लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.— लागू नहीं।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण, द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; ऐसा न होने पर सैकेण्डमेंट आधार पर स्थानान्तरण द्वारा के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा से आधार पर या संविदा के आधार पर।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.—(i) उप निदेशकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो;

(ii) हिमाचल प्रदेश सरकार/भारत सरकार/अन्य राज्य सरकारों के कर्मचारियों में से प्रथमतः एक वर्ष के लिए नियमित आधार पर समरूप वेतनमान में सदृश पदधारकों में से, सैकेण्डमैंट आधार पर/स्थानान्तरण द्वारा।

(iii) उपरोक्त स्तम्भ संख्या 10 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जो पदधारी पहले से ही सैकेण्डमैंट आधार पर लिए गए हों, को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में उनके आमेलन के लिए एक विकल्प दिया जाएगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के समाधान के अधीन वे स्तम्भ संख्या -7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता को परिपूर्ण करते हों और पदधारी, जिन्होंने आमेलन हेतु विकल्प दिया है वे पद के प्रारम्भिक संवर्ग का गठन करेंगे तथा तत्पश्चात् संख्या 10 में यथा उपबन्धित भर्ती की पद्धति अपनाई जाएगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.— अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम -3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारिस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.—जैसी समय-समय पर सरकार द्वारा गठित की जाए।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा सेवा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15—(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी को, संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी) रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर इस प्रकार चयनित व्यक्ति को सरकारी सेवा (जाब) में नियमितकरण या स्थाई आमेसन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त संयुक्त निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) को 20, 250/—रुपए की समेकित नियत रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संवत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 400/—रुपए (पद के वेतनमान में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात किए जाएंगे।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी.—सचिव, (सूचना प्रौद्योगिकी), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा पर नियुक्ति की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 20, 250/— रुपए की संविदात्मक नियत रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 400/— रुपए की (पद के वेतनमान में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा, पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी, यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदात्मक नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में, सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को, किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यदि के लिए भी हकदार नहीं होगी /होगा। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(ङ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भवती महिला/प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार: इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में विभाग में संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में नियमितिकरण/स्थाई आमेसन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. **आरक्षण.**—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गये अनुदेशों के अधीन होगी।

17. **विभागीय परीक्षा.**— सेवा में प्रत्येक सदस्य को, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

अनुबन्ध—ख

संयुक्त निदेशक, (सूचना प्रौद्योगिकी) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमतिपुत्र/पुत्री श्री निवासी
....., विदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को दिया गया।

“द्वितीय पक्षकार” ने उपरोक्त “प्रथम पक्षकार” को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में से प्रारम्भ होने और को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् दिन को स्वयंमेव ही समाप्त पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 20,250 /—रुपए (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमच मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक नियुक्ति, किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदा पर नियुक्त संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्, एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा।

7. संविदा पर नियुक्त अधिकारी का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों, दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी वेतनमान के न्यूनतम पर नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यो) को, सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ इ0 पी0 एफ0/जी0 पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति में:

1.....

.....

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति में

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No. IT-A(3)-3/2004, dated ____ November, 2008 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th November, 2008.

No. IT-A(3)-3/2004 .—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Joint Director, Class – I (Gazetted) in the Department of Information Technology, Himachal Pradesh as per **Annexure – A** attached to this notification, namely:-

1. Short title and Commencement.— 1. These rules may be called the Himachal Pradesh Information Technology Department, Joint Director, Class –I (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2008.

2. These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,

Sd/-

Secretary.

Annexure – ‘A’

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JOINT DIRECTOR, INFORMATION TECHNOLOGY IN THE DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY, GOVT. OF HIMACHAL RADESH, SHIMLA

1. Name of the Post : ‘Joint Director, Information Technology’.

2. **Number of Post(s) :** '01 (One)'.
3. **Classification :** 'Class-I (Gazetted)'.
4. **Scale of Pay :** Rs. 13500-400-15900-450-16800.
5. **Whether selection post or non-selection post :** 'Selection'.
6. **Age for direct recruits :** Between 18 to 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government of Himachal Pradesh including those who have been appointed on adhoc or on contract basis in these offices/institutions;

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis or on contract basis had become overage on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such ad hoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporations/autonomous bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/Autonomous bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note: 1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the employment exchanges or as the case may be.

Note: 2. Age and experience in the case of direct recruitment are relaxable at the discretion of the Government in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment.—
(i) Professional degree in Information Technology or engineering (B.Tech/B.E./MCA) or 'B' level course from DOEACC Society or M.Sc. with PGDCA (with additional one year experience) from a recognized University/Institute.

(ii) Experience of at least ten years in Govt./ Corporate/Pvt. Sector in the Information Technology field.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Age : N.A. Edu. Qualification : N.A.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which on secondment/by transfer basis failing both by direct recruitment on regular basis or on contract basis.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/deputation, transfer is to be made.—(i) By promotion from amongst the Deputy Director(s) who possess 03 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any in the grade;

(ii) By secondment/transfer basis from amongst the employees of Govt. of H.P./Govt. of India/other State Govt. holding analogous post in the identical pay scales on regular basis for one year in the first instance.

Notwithstanding anything contained in Col.No. 10 supra, the incumbents already taken on secondment shall be given an option for their absorption in the Department of Information Technology provided that they fulfil the educational qualification prescribed for direct recruits under Col. No. 7 subject to the satisfaction of the appointing authority and, the incumbents who opts for absorption shall form the initial cadre of the post and thereafter the methods of recruitment shall be resorted to as provided in Col. No. 10.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the posts shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *adhoc* appointment/promotion in feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that :-

- (i) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration. :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION.— The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule – 3 of Exservicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

- (2) Similarly in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into

account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment/contract appointment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if the H.P.P.S.C. or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other Recruiting Authority, as the case may be.

15-A.— Selection for appointment to the post by Contract appointment.—(I) **CONCEPT:**

(a) Under this policy, the Joint Director, IT in the Department of Information Technology, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.

(b) The Secretary (IT) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim for regularization or permanent absorption in the Government job.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Joint Director(IT) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ Rs.20,250/- P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness Pay). An amount of Rs.400/- (equal to annual increase in the pay scale of the post) as per annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Secretary (IT) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS: Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. HPPSC.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the HPPSC from time to time.

(VI) AGREEMENT: After selection of candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.— (a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.20,250/- per month. (which shall be equal to initial of the pay scale +dearness pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.400/- (equal to annual increase in the pay scale) per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularisation in service at any stage.

(d) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

(e) Unauthorised absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorised Medical Officer/Practitioner.

(h) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.

(VII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT: The candidate engaged on contract basis under these Rules shall have no right to claim regularisation/permanent absorption as Joint Director, I.T. in the Department at any stage.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass the Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules 1997.

18. Powers to relax. Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.S.C., relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

ANNEXURE – B.

Form of contract/agreement to be executed between the Joint Director, IT and the Government of Himachal Pradesh through the Director, Department of Information Technology, H.P., Shimla

This agreement is made on this _____ day of _____ in the year _____ Between Sh./Smt. _____ S/o/D/o Shri _____ R/o _____ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through the Director, Department of Information Technology, Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Joint Director, I.T. on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Joint Director, I.T. for a period of 1 year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day *i.e.* on _____ and information notice shall not be necessary.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.20,250/- per month (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness Pay).
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization of service at any stage.
5. Contractual Joint Director, I.T. will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Joint Director, I.T. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Joint Director, I.T. will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
7. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
9. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official.
10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____

(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. _____

(Name and Full Address).

शिमला-2, 18 नवम्बर, 2008

संख्या आई0टी0.-ए(3)-3/2004.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में उप निदेशक, वर्ग-1 (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न **उपाबन्ध-क** के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उप निदेशक, वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 है ।

2. ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
सचिव।

उपाबन्ध—“क”

हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में उप निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी, वर्ग—। (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.—उप निदेशक ‘सूचना प्रौद्योगिकी’।
2. पद/(पदों) की संख्या.—01 (एक)।
3. वर्गीकरण.—वर्ग — 1 (राजपत्रित)।
4. वेतनमान.—12000—375—13700—400—15500 रूपए।
5. चयन पद अथवा अचयन पद.—चयन।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी, इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण, विहित आयु में छूट का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदर्शों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—अनिवार्य अर्हता.—(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग (बी0 टैक0/बी0 ई0/एम0सी0ए0 की व्यावसायिक उपाधि या डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 (डोएक) सोसाइटी से 'बी' स्तर का कोर्स या (एक वर्ष के अतिरिक्त अनुभव के साथ) पी0जी0डी0सी0 ए0 सहित विज्ञान स्नातकोत्तर।

(ii) सरकार/नियमित/प्राइवेट सेक्टर में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कम से कम आठ वर्ष की अवधि का अनुभव।

वाँछनीय अर्हता.— हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.—आयु: लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.—लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति.—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण, द्वारा आधार पर और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता:—शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; ऐसा न होने पर सैकण्डमैंट आधार पर/स्थानान्तरण द्वारा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा से आधार पर या संविदा के आधार पर।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.—(i) प्रबन्धकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित दशा सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो;

(ii) हिमाचल प्रदेश सरकार/भारत सरकार/अन्य राज्य सरकारों के कर्मचारियों में से प्रथमतः एक वर्ष को नियमित आधार पर समरूप वेतनमान में सदृश पदधारकों में से सैकण्डमैंट आधार पर/स्थानान्तरण द्वारा।

उपरोक्त स्तम्भ संख्या 10 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जो पदधारी पहले से ही सैकण्डमैंट आधार पर लिए गए हों, को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में उनके आमेदन के लिए एक विकल्प दिया जाएगा यदि नियुक्ति प्राधिकारी समाधान के अधीन वे स्तम्भ संख्या-7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता को परिपूर्ण करते हों और पदधारी, जिन्होंने आमेदन हेतु विकल्प दिया है वे पद के प्रारम्भिक संवर्ग का गठन करेंगे तथा तत्पश्चात् स्तम्भ 10 में यथा उपबन्धित भर्ती की पद्धति अपनाई जाएगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने —अपने प्रवर्ग/पद/काडर में

उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम -3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारिस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.—जैसी समय-समय पर सरकार द्वारा गठित की जाए।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा सेवा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में प्रबन्धक सूचना प्रौद्योगिकी को, संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी) रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर इस प्रकार चयनित व्यक्ति को, सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेसन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त संयुक्त निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) को 18,000/—रुपए की समेकित नियत रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संवत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 375/— रुपए (पद के वेतनमान में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात किए जाएंगे।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी.—सचिव, (सूचना प्रौद्योगिकी) हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा पर नियुक्ति की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 18,000/— रुपए की संविदात्मक नियत रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 375/— रुपए की (पद के वेतनमान में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे, वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा, पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी, यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदात्मक नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में, सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को, किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यदि के लिए भी हकदार नहीं होगी/होगा। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

(ङ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदों पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भवती महिला/प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर

अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार.—इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में विभाग में उप निदेशक, प्रबन्ध, सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में नियमितिकरण/स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. **आरक्षण.**—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गये अनुदेशों के अधीन होगी।

17. **विभागीय परीक्षा.**—सेवा में प्रत्येक सदस्य को हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. **शिथिल करने की शक्ति .**—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध—ख

उप निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमतिपुत्र/पुत्री श्री.....निवासी ...
....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **“प्रथम पक्षकार”** कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य.....(नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् **“द्वितीय पक्षकार”** कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को दिया गया।

“द्वितीय पक्षकार” ने उपरोक्त **“प्रथम पक्षकार”** को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने उप निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में संविदा के आधार पर, निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार उन निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी के रूप मेंसे प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्.....दिन को स्वयंमेव ही समाप्त पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 18,000/—रुपए (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर

दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक नियुक्ति, किसी भी दशा में नियमितकरण के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदा पर नियुक्त उप निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्, एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त उप निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा।

7. संविदा पर नियुक्त अधिकारी का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को, सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी वेतनमान के न्यूनतम पर नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को, सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ इ0 पी0 एफ0/जी0 पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप **प्रथम पक्षकार** और **द्वितीय पक्षकार** ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में:

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

साक्षी की उपस्थिति में

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No. IT-A(3)-3/2004, dated.....November, 2008 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th November, 2008

No. IT-A(3)-3/2004.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Deputy Director, Class – I (Gazetted) in the Department of Information Technology, Himachal Pradesh as per **Annexure–A** attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—1. These rules may be called the Himachal Pradesh Information Technology Department, Deputy Director, Class –I (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2008.

2. These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,
Sd/-
Secretary.

ANNEXURE – ‘A’

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR, INFORMATION TECHNOLOGY IN THE DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY, GOVT. OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

- 1. Name of the Post.**—‘Deputy Director, Information Technology’.
- 2. Number of Post(s).**—‘01 (One)’.
- 3. Classification.**— ‘Class-I (Gazetted)’.
- 4. Scale of Pay.**—Rs.12000-375-13500-400-15500.
- 5. Whether selection post or non-selection post.**—‘Selection’.
- 6. Age for direct recruits.**—Between 18 to 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government of Himachal Pradesh including those who have been appointed on adhoc or on contract basis in these offices/institutions;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such ad hoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporations/autonomous bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note-1.— Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the employment exchanges or as the case may be.

Note-2.— Age and experience in the case of direct recruitment are relaxable at the discretion of the Government in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment.—(i) Professional degree in Information Technology or engineering (B.Tech/ B.E./ MCA) or 'B' level course from DOEACC Society or M.Sc. with PGDCA (with additional one year experience) from a recognized University/Institute.

(ii) Experience of at least eight years in Govt./Corporate/Pvt. Sector in the Information Technology field.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Age.—N.A.

Edu. Qualification.—N.A.

9. Period of probation if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which on secondment/by transfer basis failing both by direct recruitment on regular basis or on contract basis.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/ deputation, transfer is to be made.—i) By promotion from amongst the Managers who possess 03 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any in the grade;

(ii) By secondment/transfer basis from amongst the employees of Govt. of H.P./Govt. of India/other State Govt. holding analogous post in the identical pay scales on regular basis for one year in the first instance.

Notwithstanding anything contained in Col.No. 10 supra, the incumbents already taken on secondment shall be given an option for their absorption in the Department of Information Technology provided that they fulfil the educational qualification prescribed for direct recruits under Col. No. 7 subject to the satisfaction of the appointing authority and, the incumbents who opts for absorption shall form the initial cadre of the post and thereafter the methods of recruitment shall be resorted to as provided in Col. No. 10.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the posts shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that :—

(i) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less; Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule – 3 of Exservicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment/ contract appointment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva voce test,

if the H.P.P.S.C. or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other Recruiting Authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by Contract appointment.—
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Deputy Director, IT in the Department of Information Technology, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.

(b) The Secretary(IT) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim for regularization or permanent absorption in the Government job.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Deputy Director(IT) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ Rs.18,000/- P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness Pay). An amount of Rs.375/- (equal to annual increase in the pay scale of the post) as per annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Secretary (IT) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. HPPSC.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the HPPSC from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.18,000/- per month. (which shall be equal to initial of the pay scale +dearness pay. The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.375/- (equal to annual increase in the pay scale) per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularisation in service at any stage.

(d) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

(e) Unauthorised absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for the fitness from an authorised Medical Officer/Practitioner.

(h) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.

(VII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT.—The candidate engaged on contract basis under these Rules shall have no right to claim regularisation/permanent absorption as Deputy Director, I.T. in the Department at any stage.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass the Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules 1997.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C., relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

ANNEXURE-B.

Form of contract/agreement to be executed between the Deputy Director, IT and the Government of Himachal Pradesh through the Director, Department of Information Technology, H.P., Shimla

This agreement is made on this _____ day of _____ in the year _____. Between Sh./Smt. _____ S/o/D/o Shri _____ R/o _____

Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through the Director, Department of Information Technology, Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Deputy Director, I.T. on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Deputy Director, I.T. for a period of 1 year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day *i.e.* on _____ and information notice shall not be necessary.
2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.18,000/- per month (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness Pay).
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization of service at any stage.
5. Contractual Deputy Director, I.T. will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Joint Director, I.T. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Deputy Director, I.T. will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
7. Transfer of an official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.
8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
9. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official.
10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____

(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. _____

(Name and Full Address)

शिमला-2, 18 नवम्बर, 2008

संख्या आई0टी0बी(3) / 2004.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में संयुक्त निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न **उपाबन्ध-क** के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग संयुक्त निदेशक, वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2008 है ।

2. ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / —
सचिव ।

उपाबन्ध-“क”

हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में प्रबन्धक, सूचना प्रौद्योगिकी के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**—प्रबन्धक, सूचना प्रौद्योगिकी ।

2. **पदों की संख्या.**—2 (दो) ।

3. **वर्गीकरण.**—वर्ग-1 (राजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं)

4. **वेतनमान.**—10025—275—10300—340—12000—375—13500—400—15100 रुपए ।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.—चयन।**6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—45 वर्ष या इससे कम।**

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी, इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्तर्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार षिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—अनिवार्य अर्हता(एँ).—(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजिनियरिंगकम्प्यूटर एपलिकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष।

(ii) सरकार/निगम/निजी सेक्टर में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कम से कम छः वर्ष की अवधि का अनुभव।

या

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक/गणित में स्नातकोन्तर या इसके समकक्ष।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर एपलिकेशन में स्नातकोन्तर डिप्लोमा या इसके समकक्ष।

(iii) सरकार निगम (कॉर्पोरेट) निजी क्षेत्र सेक्टर में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कम से कम सात वर्ष की अवधि का अनुभव।

या

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश/केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर विज्ञान में विज्ञान स्नातकोत्तर। एम. सी. ए. या इसके समकक्ष।

(ii) सरकार निगम (कॉर्पोरेट)/निजी सैक्टर में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कम से कम पाँच वर्ष की अवधि का अनुभव।

या

(i) डोएक (डी. ओ. ई. ए. सी. सी.) समिति से 'बी' स्तर का कोर्स।

(ii) सरकार/निगम (कॉर्पोरेट) निजी सैक्टर में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कम से कम पाँच वर्ष की अवधि का अनुभव।

2. वाँछनीय अर्हता(एँ).—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू या नहीं.— आयु.—लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.—हाँ, लागू हैं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति.—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण, द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—(i) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; और

(ii) पचास प्रतिशत सैकण्डमैन्ट आधार/स्थानान्तरण द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.—(i) सूचना प्रौद्योगिकी में से, उपरोक्त स्तम्भ संख्या-7 के सामने सीधी भर्ती के लिए यथाविहित शैक्षिक अर्हताओं को परिपूर्ण करने के अध्यधीन जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवा कार्य या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा।

(ii) हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/भारत सरकार/अन्य राज्य सरकारों से समरूप वेतनमान में सदृश पद धारक पदधारियों में से सैकण्डमैन्ट आधार/स्थानान्तरण द्वारा।

(iii) उपरोक्त स्तम्भ संख्या 10 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पहले से ही सैकण्डमैन्ट आधार पर लिए पदधारियों को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में उनके आमेदन के लिए एक विकल्प दिया जाएगा, परन्तु स्तम्भ संख्या-7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता, नियुक्त प्राधिकारी के समाधान के अध्यधीन परिपूर्ण करते हों और पदधारी जिन्होंने आमेदन हेतु विकल्प दिया है वह प्रबन्धक, सूचना प्रौद्योगिकी के पद के प्रारम्भिक संवर्ग का गठन करेंगे और उसके पश्चात् उपरोक्त स्तम्भ संख्या-10 में यथा विहित भर्ती की प्रवृत्ति अपनाई जाएगी। इस पद के सदृश और वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों में से सैकण्डमैन्ट आधार पर।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन

रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:—अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारिस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.—जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती संविदा पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा सेवा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15—(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—(I) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में प्रबन्धक सूचना प्रौद्योगिकी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.—सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी/हिमाचल प्रदेश सरकार) रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर इस प्रकार चयनित व्यक्ति को, सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेसन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.—संविदा के आधार पर नियुक्त प्रबन्धक, सूचना प्रौद्योगिकी को 15,038/—रुपए की समेकित नियत रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संवत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 275/—रुपए (पद के वेतनमान में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात किए जाएंगे।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.—संविदा पर नियुक्ति की दशा में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 15,038/— रुपए की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 275/— रुपए की (पद के वेतनमान में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा, पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी, यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदा पर नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में, सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को, किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगी/होगा। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ङ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का (पर्यावसान) समापन हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भवती महिला/अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार.—इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में विभाग में प्रबन्ध, सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में नियमितिकरण/स्थाई आमेसन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गये अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—सेवा में प्रत्येक सदस्य को, समय-समय पर संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति(व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद(पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध—ख

प्रबन्धक, सूचना प्रौद्योगिकी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य (निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमतिपुत्र/पुत्री श्री
निवासीसंविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल के मध्य (निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख को दिया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त "प्रथम पक्षकार" को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने
(प्रबन्धक, सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में संविदा के आधार पर, निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार (प्रबन्धक, सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप मेंसे प्रारम्भ होने और को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्.....दिन को स्वयंमेव ही समाप्त पर्यवसित समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 15,038/—रुपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्त के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति (समाप्त) पर्यवसित की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदात्मक नियुक्ति, किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
5. संविदा पर नियुक्त (प्रबन्धक, सूचना प्रौद्योगिकी) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्, एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त (प्रबन्धक, सूचना प्रौद्योगिकी) को, किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अन्धकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का (समापन पर्यावसान) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त (प्रबन्धक, सूचना प्रौद्योगिकी) कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा।
7. संविदा पर नियुक्त अधिकारी का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।
8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों, दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को, सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ इ0 पी0 एफ0/जी0 पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा।
11. इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.
.....
2.
.....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.

.....

2.

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No. IT-A(3)-1/2004, dated 18th November, 2008 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th November, 2008

No. IT-A(3)-1/2004.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Manager, Class-I (Gazetted) in the Department of Information Technology, Himachal Pradesh as per **Annexure – A** attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—1. These rules may be called the Himachal Pradesh Information Technology Department, Manager, Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2008.

2. These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By Order,
Sd/-
Secretary.

ANNEXURE – ‘A’

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF MANAGER,
INFORMATION TECHNOLOGY IN THE DEPARTMENT OF INFORMATION
TECHNOLOGY, GOVT. OF HIMACHAL RADESH, SHIMLA**

- 1. Name of the Post.**—‘Manager, Information Technology’.
- 2. Number of Post(s).**—‘02 (Two)’.
- 3. Classification.**—‘Class-I (Gazetted)(Non-Ministerial Services)’.
- 4. Scale of Pay.**—Rs.10025-275-10300-340-12000-375-13500-400-15100.
- 5. Whether selection post or non-selection post.**—‘Selection’.

6. Age for direct recruits.—45 years and below.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government of Himachal Pradesh including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on ad hoc basis or on contract basis had become overage on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such *ad hoc* or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial of such constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporations/autonomous and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the employment exchanges or as the case may be.

Note.—2. Age and experience in the case of direct recruitment are relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment.—
Essential Qualification(s).— i) Bachelor's Degree in Computer Science & Engineering/Computer Application/Information Technology or its equivalent from a recognised University or from an Institute duly recognised by the H.P. / Central Government.

ii) Experience of at least six years duration in information technology field in Government/Corporate / Private Sector.

OR

(i) M.Sc. in Physics / Mathematics or its equivalent from a recognised University.

(ii) Post Graduate Diploma in Computer Application or its equivalent from a recognised University or from an Institute duly recognised by the H.P./Central Government.

(iii) Experience of at least seven years duration in information technology field in Government/Corporate / Private Sector.

OR

(i) M.Sc. in Information Technology/Computer Science / MCA or its equivalent from a recognised University or from an Institute duly recognised by the H.P. / Central Government.

(ii) Experience of at least five years duration in information technology field in Government/Corporate / Private Sector.

OR

(i) “B” level Course from DOEACC Society.

(ii) Experience of at least five years duration in information technology field in Government/Corporate / Private Sector.

Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Age : Not Applicable.

Edu. Qualification.—Yes.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment-whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—50% by promotion; and 50% by secondment/by transfer basis failing which by direct recruitment.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/deputation, transfer is to be made.—i) By promotion from amongst the Deputy Managers, Information Technology subject to fulfilling the educational qualifications as prescribed for the direct recruitment against Column No.7 above with three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

(ii) By secondment/by transfer basis from amongst the incumbents holding analogous post in the identical pay scales from other Departments of H.P. Government/Government of India/Other State Governments.

(iii) Notwithstanding anything contained in Col.No. 10 *supra*, the incumbents already taken on secondment shall be given an option for their absorption in the Department of Information Technology provided that they fulfil the educational qualification prescribed for direct recruits under Col. No. 7 above and subject to the satisfaction of the appointing authority and, the incumbents who opts for absorption may form the initial cadre of the post of Manager, Information Technology and thereafter the methods of recruitment shall be resorted to as prescribed in Col. No. 10 above.

(1) In all cases of promotion, the continuous *adhoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the posts shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *adhoc* appointment/promotion in feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that :—

(i) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Exservicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly in all cases of confirmation continuous *adhoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *adhoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that *inter-se-seniority* as a result of confirmation after taking into account, *adhoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?

As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment/contract appointment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva-voce* test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so considers necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by Contract appointment.—(I) **CONCEPT.**—(a) Under this policy, the Manager, IT in the Department of Information Technology, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC The Secretary(IT) to the Government of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim for regularization or permanent absorption in the Government job.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Manager, IT appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ Rs.15,038/- P.M. (which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness Pay). An amount of Rs.275/- (equal to annual increase in the pay scale of the post) as per annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Secretary(IT) to the Government of H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of *viva-voce* test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* HPPSC.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.—As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the HPPSC from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.15,038/- per month. (which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay. The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 275/- (equal to annual increase in the pay scale) per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularisation in service at any stage.

(d) Contract Appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per rules.

(e) Unauthorised absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit until the confinement is over. The woman candidate will be re-examined for

the fitness from an authorised Medical Officer/Practitioner.

(h) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.

(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT.—The candidate engaged on contract basis under these Rules shall have no right to claim regularisation/permanent absorption as Manager, I.T. in the Department at any stage.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules 1997 as amended from time to time.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.S.C., relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

ANNEXURE–B.

Form of contract/agreement to be executed between the Manager, I.T. and the Government of Himachal Pradesh through the Director, Department of Information Technology, H.P., Shimla

This agreement is made on this _____ day of _____ in the year _____. Between Sh./Smt. _____ S/o/D/o Shri _____ R/o _____

_____ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through the Director, Department of Information Technology, Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Manager, I.T. on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Manager, I.T. for a period of 1 year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.15,038/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization of service at any stage.

5. Contractual Manager, I.T. will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Manager, I.T. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Manager, I.T. will not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

9. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official.

10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

 (Name and Full Address)

2. _____

 (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

 (Name and Full Address)

2. _____

 (Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

लोक निर्माण विभाग**अधिसूचनाएं**

शिमला-2, 17 नवम्बर, 2008

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5)182/2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव पुरखेहड, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में रानीताल-कोटला सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ0 क्षेत्र कांगड़ा) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (है0 में) |
|---------|--------|---------|------------|--------------------|
| कांगड़ा | ज्वाली | पुरखेहड | 341 / 1 | 0-07-80 |
| | | | 369 / 1 | 0-02-25 |
| | | | 370 / 1 | 0-02-87 |
| | | | 374 / 1 | 0-05-48 |
| | | | 561 | 0-00-69 |
| | | | 564 / 1 | 0-03-12 |
| | | | 565 / 1 | 0-01-32 |
| | | | 593 / 1 | 0-00-39 |
| | | | कुल किता 8 | 0-23-92 |

शिमला-2, 17 नवम्बर, 2008

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5)179/2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव सेर खैरियां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में रानीताल-कोटला सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4 कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ० क्षेत्र कांगड़ा) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (है० में) |
|---------|--------|---------|--------------|--------------------|
| कांगड़ा | ज्वाली | खैरियां | 64 / 1 | 0-00-60 |
| | | | 73 / 1 | 0-00-48 |
| | | | 76 / 1 | 0-00-26 |
| | | | 78 / 1 | 0-01-36 |
| | | | 531 / 79 / 1 | 0-00-32 |
| | | | 80 / 1 | 0-00-25 |
| | | | 80 / 2 | 0-00-77 |
| | | | 92 / 2 / 1 | 0-00-92 |
| | | | 93 / 1 | 0-00-38 |
| | | | 94 / 1 | 0-00-03 |
| | | | 95 / 1 | 0-00-33 |
| | | | 155 / 1 | 0-00-35 |
| | | | 156 / 1 | 0-01-10 |
| | | | 158 / 1 | 0-02-25 |
| | | | 165 / 1 | 0-00-38 |
| | | | 166 / 1 | 0-00-30 |
| | | | 169 / 1 | 0-00-36 |
| | | | 170 / 1 | 0-00-61 |
| | | | 200 / 1 / 1 | 0-00-42 |
| | | | 208 / 1 | 0-00-16 |
| | | | 209 / 1 | 0-00-56 |
| | | | 210 / 1 | 0-00-42 |
| | | | 212 / 1 | 0-00-08 |
| | | | 213 / 1 | 0-00-23 |
| | | | 214 / 1 | 0-00-20 |
| | | | 215 / 1 | 0-00-03 |
| | | | 216 / 1 | 0-00-36 |
| | | | 217 / 1 | 0-00-54 |
| | | | 218 / 1 | 0-00-22 |
| | | | 229 / 1 | 0-01-02 |
| | | | 230 / 1 | 0-00-26 |
| | | | 231 / 1 | 0-00-96 |
| | | | 232 / 1 | 0-01-32 |
| | | | 246 / 1 | 0-00-60 |
| | | | 264 / 1 | 0-00-11 |
| | | | 265 / 1 | 0-00-84 |

| | |
|-------------|---------|
| 268 / 1 | 0-00-25 |
| 354 / 1 | 0-00-33 |
| 355 / 1 | 0-02-67 |
| 360 / 1 | 0-00-98 |
| 361 / 1 | 0-00-42 |
| 362 / 1 | 0-00-19 |
| 314 / 1 | 0-01-62 |
| 351 / 1 | 0-00-56 |
| 354 / 2 | 0-00-38 |
| कुल किता 42 | 0-26-78 |

शिमला-2, 17 नवम्बर, 2008

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5)180 / 2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव भरमाडा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में रानीताल-कोटला सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ0 क्षेत्र कांगड़ा) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (है0 में) |
|---------|--------|--------|------------|--------------------|
| कांगड़ा | ज्वाली | भरमाडा | 37 / 1 | 0-01-19 |
| | | | 86 / 1 | 0-00-72 |
| | | | 87 / 1 | 0-00-64 |
| | | | 88 / 1 | 0-01-38 |
| | | | 141 / 1 | 0-00-79 |
| | | | 142 / 1 | 0-00-48 |
| | | | 143 / 1 | 0-00-51 |
| | | | 143 / 2 | 0-00-72 |
| | | | 209 / 1 | 0-00-11 |
| | | | 210 / 1 | 0-00-42 |
| | | | 213 / 1 | 0-01-06 |
| | | | 214 / 1 | 0-00-07 |
| | | | 222 / 1 | 0-02-45 |
| | | | 230 / 1 | 0-00-27 |
| | | | 231 / 1 | 0-03-98 |

| | |
|-------------|---------|
| 234 / 1 | 0-00-40 |
| 265 / 1 | 0-00-78 |
| 266 / 1 | 0-00-88 |
| 267 / 1 | 0-00-71 |
| 299 / 1 | 0-00-41 |
| 300 / 1 | 0-00-68 |
| 301 / 1 | 0-02-46 |
| 321 / 1 | 0-00-42 |
| 322 / 1 | 0-00-10 |
| कुल किता 24 | 0-21-63 |

शिमला-2, 17 नवम्बर, 2008

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5)183/2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव कुठेहड, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में रानीताल-कोटला सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ0 क्षेत्र कांगड़ा) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (है0 में) |
|---------|--------|--------|-----------------|--------------------|
| कांगड़ा | ज्वाली | भरमाडा | 2308 / 36 / 1 | 0-00-27 |
| | | | 2338 / 2309 / 1 | 0-00-14 |
| | | | 2339 / 2309 / 1 | 0-00-14 |
| | | | 2340 / 2309 / 1 | 0-02-76 |
| | | | 2340 / 2309 / 2 | 0-00-60 |
| | | | 2340 / 2309 / 3 | 0-00-60 |
| | | | 2340 / 2309 / 4 | 0-00-38 |
| | | | 37 / 1 | 0-00-10 |
| | | | 66 / 1 | 0-01-11 |
| | | | 67 / 1 | 0-00-86 |
| | | | 68 / 1 | 0-00-01 |
| | | | 69 / 1 | 0-00-10 |
| | | | 2310 / 71 / 1 | 0-00-24 |
| | | | 2311 / 71 / 1 | 0-00-06 |
| | | | 2312 / 71 / 1 | 0-00-12 |

| | |
|-----------------|---------|
| 2313 / 71 / 1 | 0-00-06 |
| 72 / 1 | 0-00-55 |
| 80 / 1 | 0-00-20 |
| 81 / 1 | 0-00-09 |
| 82 / 1 | 0-00-54 |
| 86 / 1 | 0-02-35 |
| 87 / 1 | 0-00-86 |
| 2315 / 90 / 1 | 0-00-09 |
| 2316 / 90 / 1 | 0-00-18 |
| 2317 / 90 / 1 | 0-00-36 |
| 2345 / 2318 / 1 | 0-00-09 |
| 88 / 1 | 0-00-23 |
| 2346 / 2318 / 1 | 0-00-38 |
| 2346 / 2318 / 2 | 0-00-73 |
| 91 / 1 | 0-01-16 |
| 103 / 1 | 0-00-43 |
| 105 / 1 | 0-00-18 |
| 106 / 1 | 0-00-22 |
| 107 / 1 | 0-00-86 |
| 109 / 1 | 0-03-11 |
| 112 / 1 | 0-04-74 |
| 114 / 1 | 0-02-62 |
| 200 / 1 | 0-02-70 |
| 201 / 1 | 0-01-28 |
| 202 / 1 | 0-00-24 |
| 206 / 1 | 0-02-59 |
| 2347 / 222 / 1 | 0-00-40 |
| 2348 / 222 / 1 | 0-00-7 |
| 2349 / 222 / 1 | 0-00-12 |
| 2350 / 222 / 1 | 0-00-12 |
| 2351 / 222 / 1 | 0-00-06 |
| 2352 / 222 / 1 | 0-00-05 |
| 2353 / 222 / 1 | 0-01-01 |
| 225 / 1 | 0-00-10 |
| 226 / 1 | 0-00-09 |
| 228 / 1 | 0-00-05 |
| 2341 / 2314 / 1 | 0-00-20 |
| 229 / 1 | 0-00-06 |
| 290 / 1 | 0-01-46 |
| 291 / 1 | 0-00-23 |
| 294 / 1 | 0-00-41 |
| 295 / 1 | 0-00-26 |
| 297 | 0-00-30 |
| 299 / 1 | 0-00-19 |
| 300 / 1 | 0-01-61 |
| 304 / 1 | 0-00-38 |
| 305 / 1 | 0-00-81 |
| 307 / 1 | 0-00-63 |
| 308 / 1 | 0-00-22 |

| | |
|-------------|---------|
| 309 / 1 | 0-00-23 |
| 310 / 1 | 0-00-08 |
| 314 / 1 | 0-00-22 |
| 335 / 1 | 0-01-70 |
| 336 / 1 | 0-01-53 |
| 339 / 1 | 0-00-83 |
| 343 / 1 | 0-00-77 |
| 344 / 1 | 0-00-38 |
| 345 / 1 | 0-00-42 |
| 1677 / 1 | 0-00-06 |
| 1978 / 1 | 0-00-56 |
| 1685 / 1 | 0-00-29 |
| 1698 / 1 | 0-01-10 |
| 1699 / 1 | 0-00-48 |
| 1700 / 1 | 0-00-53 |
| 1799 / 1 | 0-00-26 |
| 1808 / 1 | 0-00-30 |
| 1826 / 1 | 0-00-69 |
| 1828 / 1 | 0-00-85 |
| 1832 / 1 | 0-00-96 |
| 1842 / 1 | 0-00-77 |
| 1960 / 1 | 0-01-41 |
| 1963 / 1 | 0-00-87 |
| 1964 / 1 | 0-01-23 |
| 1966 / 1 | 0-00-22 |
| 1967 / 1 | 0-00-12 |
| 1967 / 2 | 0-00-14 |
| 1990 / 1 | 0-00-56 |
| 1991 / 1 | 0-00-86 |
| 1992 / 1 | 0-00-98 |
| 1993 / 1 | 0-00-20 |
| कुल किता 95 | 0-62-76 |

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2008

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5)193/2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव अमरेडा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना में ऊना-अग्धार-मण्डी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4 कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ० क्षेत्र कांगड़ा) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (है० में) |
|------|--------|--------|---------------|--------------------|
| ऊना | बंगाणा | अमरेडा | 71 / 1 | 0-00-10 |
| | | | 75 / 1 | 0-00-14 |
| | | | 76 / 1 | 0-00-18 |
| | | | 77 / 1 | 0-00-30 |
| | | | 313 / 1 | 0-02-79 |
| | | | 318 / 1 | 0-01-29 |
| | | | 326 / 1 | 0-00-03 |
| | | | 357 / 319 / 1 | 0-00-55 |
| | | | 320 / 1 | 0-01-05 |
| | | | कुल किता 9 | 0-06-43 |

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2008

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5)191 / 2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव घडो, तहसील बंगाणा, जिला ऊना में ऊना-अग्धार-मण्डी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4 कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, (उ० क्षेत्र कांगड़ा) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

| जिला | तहसील | गांव | खसरा नम्बर | क्षेत्र (है० में) |
|------|--------|------|------------|--------------------|
| ऊना | बंगाणा | घडो | 363 / 1 | 0-00-51 |
| | | | कुल किता 1 | 0-00-51 |

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
सचिव।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

हेम राज पुत्र श्री बंगाली राम, जात राजपूत, साकन जमथल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि० प्र०)
... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में भेजकर लिखा जाता है कि श्री हेम राज पुत्र श्री बंगाली, निवासी जमथल ने अधोहस्ताक्षरी की न्यायालय में आवेदन-पत्र दायर किया है कि उसके पुत्र रमन ठाकुर की जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है। अतः अब उसे दर्ज करने के आदेश देने की अनुकम्पा करें।

अतः इस इशतहार राजपत्र के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को श्री रमन ठाकुर पुत्र श्री हेम राज, निवासी जमथल की जन्म तिथि दिनांक 18-7-2008 ग्राम पंचायत धौण कोठी के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति दिनांक 6-12-2008 को असालतन/ वकालतन अधोहस्ताक्षरी की न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। इसके उपरान्त किसी किस्म की आपत्ति समायत न होगी तथा उपरोक्त तिथि को दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 10-11-2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) सदर,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

शेर सिंह बल्द कलू राम, जात राजपूत, साकन सोलग जुरासी परगना व तहसील सदर, जिला बिलासपुर
(हि० प्र०)

... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्री शेर सिंह पुत्र श्री कालू राम, जाति राजपूत, निवासी गांव सोलग जुरासी परगना व तहसील सदर, जिला बिलासपुर ने अधोहस्ताक्षरी की न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री रक्षा पत्नी श्री मनोज कुमार ने उसके घर बच्चे को दिनांक 21-12-2004 को जन्म दिया था। लेकिन बच्चे की जन्म तिथि का इन्द्राज पंचायत अभिलेख में नहीं करवाया जा सका क्योंकि रक्षा देवी की मृत्यु हो गई थी। अतः अब बच्चे सिकन्दर पुत्र श्री मनोज की जन्म तिथि का इन्द्राज पंचायत अभिलेख में इन्द्राज करने का आदेश देने की अनुकम्पा करें।

अतः इस इशतहार राजपत्र के द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को सिकन्दर पुत्र श्री मनोज कुमार की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत धार टटोह के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना उजर/एतराज दिनांक 6-12-2008 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी की न्यायालय में असालतन/वकालतन पेश कर सकता है। उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए श्री सिकन्दर पुत्र श्री मनोज की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत धार टटोह के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 10-11-2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) सदर,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate Ghumarwin, District Bilaspur
(H. P.)**

In the Matter of :

1. Shri Ravinder Kumar, age 35 years s/o Shri Prema Ram, resident of Village Baloh, P. O. Bari Majerwan, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.).
2. Saroj Kumari, age 33 years d/o Shri Brij Lal, resident of Village Panyala, P. O. Kothi, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.)
.. Applicants.

Versus

General Public.

Subject.—Application for the Registration of Marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01 (49 of 2001).

Shri Ravinder Kumar age 35 years s/o Shri Prema Ram, resident of Village Baloh, P. O. Bari Majerwan, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh and Saroj Kumari, age 33 years d/o Shri Brij Lal, resident of Village Panyala, P. O. Kothi, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavit in the Court of under signed under section 16 of Special Marriage Act 1954, (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01 (49 of 2001). That they have solemnized their marriage 19-7-2007 at Arya Lower Bazar Shimla Himachal Pradesh and they are living together as husband and wife since then. Hence there marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore the General Public is hereby informed through this Notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 15-12-2008 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 31-10-2008 under my hand and seal of the Court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.).

ब अदालत श्री नजीर खान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।

तारीख पेशी : 29-12-2008.

श्री धोवू राम पुत्र श्री सरदारी लाल, निवासी तकरेहड़, डाकघर सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्री धोवू राम पुत्र श्री सरदारी लाल ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल तकरेहड़, उप-तहसील सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरे पिता का नाम सरदारु लिखा गया है जो गलत है। मेरे पिता का वास्तविक नाम सरदारी लाल है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 29-12-2008 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। वसूरत गैर-हाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 6-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नजीर खान,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता,
द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री नजीर खान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।

तारीख पेशी : 29-12-2008.

श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री भूप चन्द, निवासी फनैहल, डाकघर कुज्जवलह, उप-तहसील सन्धोल,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम।

श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री भूप चन्द ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल फनैहल, उप-तहसील सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरे पति का नाम भूरु लिखा गया है जो गलत है। मेरे पति का वास्तविक नाम भूप चन्द है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 29-12-2008 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। वसूरत गैर-हाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इशतहार आज दिनांक 6-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नजीर खान,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता,
द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री नजीर खान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सन्धोल,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।

तारीख पेशी : 29-12-2008.

श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री यश पाल, निवासी लोअर वैरी, डाकघर कोहूवा, उप-तहसील
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री यश पाल, निवासी लोअर वैरी, डाकघर कोहूवा, उप-तहसील
सन्धोल ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल लोअर वैरी, उप-तहसील
सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरे पति का नाम भूरि सिंह लिखा गया है जो गलत है। मेरे पति का वास्तविक
नाम यश पाल है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम
दरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक
29-12-2008 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। वसूरत
गैर-हाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इशतहार आज दिनांक 6-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नजीर खान,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता,
द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री नजीर खान, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सन्धोल,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।

तारीख पेशी : 29-12-2008.

श्री राजमल पुत्र श्री रेलू राम, निवासी बल्ह, डाकघर धलारा, उप-तहसील सन्धोल, जिला मण्डी
(हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम।

श्री राजमल ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल बल्ह, उप-तहसील सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम राज सिंह लिखा गया है जो गलत है। मेरा वास्तविक नाम राजमल है। इसकी दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 29-12-2008 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। वसूरत गैर-हाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इशतहार आज दिनांक 7-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नजीर खान,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता,
द्वितीय श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अशोक चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री सन्जू and d/o Shri हरि राम, r/o खजराल, P. O. गुम्मा, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

ग्राम पंचायत रोपा पधर

जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री सन्जू राम, and d/o Shri हरि राम, r/o खजराल, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिन का जन्म दिनांक 7-3-1979 व उसके पुत्र निखिल का जन्म दिनांक 18-1-2002 को हुआ है। परन्तु इनकी जन्म तिथियां व नाम ग्राम पंचायत, रोपा पधर के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई हैं। जिसे अब दर्ज करने के आदेश सादर फरमाये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम व जन्म तिथियां दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 3-12-2008 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एजराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथियां व नाम दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 3-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

अशोक चौहान,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, जोगिन्दरनगर,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री एम0 डी0 राकेश, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर मण्डी,
जिला मण्डी, (हि0 प्र0)

श्री तवारसू पुत्र श्रीमती चैतरी, निवासी डमायहर, डाकघर कमान्द, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, अधिनियम, 1969.

श्री तवारसू पुत्र श्रीमती चैतरी, निवासी डमायहर, डाकघर कमान्द, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उनका स्वयं का तपारसू पुत्र श्रीमती चैतरी, का जन्म दिनांक 23-9-1972 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कमान्द के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-12-2008 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री तवारसू पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 10-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

एम0 डी0 राकेश,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर मण्डी,
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

कमला देवी पुत्री श्री सन्त राम, निवासी कनैड़, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
.. प्रार्थनी।

बनाम

रूप लाल आदि

.. प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र तकसीम।

कमला देवी प्रार्थनी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह भूमि खैवट नम्बर 514, खतौनी नम्बर 603, कित्ता-7, रकवा तादादी 6-7-17 में से अपना हिस्सा की तकसीम कराना चाहती है।

प्रत्यार्थीगण नम्बर 12 रीना देवी, 13 मीना देवी पुत्रियां श्री सुन्दरू, निवासी हलेल, डाकघर कनेड़, तहसील सुन्दरनगर को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उन्हें तकसीम

कराने हेतु कोई उजर/एतराज हो तो दिनांक 26-12-2008 को इस अदालत में पेश होकर उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 10-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी),
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

**In the Court of Shri K. K. Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan
Himachal Pradesh**

Case No.
17/2008

Date of Institution
10-9-2008

Date of decision
Pending for
6-12-2008

Shri Virender s/o of Shri Surjit Singh, resident of Village Taksal, Pargana Bhaget, Tehsil Kasauli,
District Solan (H. P.) . . Applicant.

Vs.

General Public

. . Respondent.

APPLICATION UNDER SECTION 13 (3) OF BIRTH & DEATH REGISTRATION ACT, 1969

Shri Virender s/o of Shri Surjit Singh, resident of Village Taksal, Pargana Bhaget, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents, stating therein that his daughter named Km. Kritee was born on 6-5-2003 at Village Taksal, Pargana Bhaget, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but her date of birth could not be registered by the applicant in Gram Panchayat's record, Taksal, Tehsil Kasauli.

2. Therefore, by this proclamation the general public is hereby directed that any person having any objection for the registration of date of birth of Km. Kritee daughter of the applicant may submit his objection in writing in this court on or before 6-12-2008 at 10 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court this 10th September, 2008.

Seal.

K. K. SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan (H. P.).